

रजिस्ट्री सं. डी. एल-33004/99
15/9/04

R-10544
राजस्व संस्कार अधिनियम
प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया अधिनियम
को प्रधानमंत्री द्वारा प्रकाशित किया गया

REGD. NO. D.L.-33004/99



प्रभारी

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.D.—350

K.M.—30

Def.H.—100

C.P.—250

सं. 291]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2004/आषाढ़ 21, 1926

No. 291]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2004/ASADHA 21, 1926

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2004

सा.का.नि. 446(अ).—राष्ट्रपति द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप-धारा(2) के तहत किए गए निम्नलिखित आदेश को जैसा कि उस धारा के अधीन अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात्:-

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में एक स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 2004

राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तमिलनाडु के राज्यपाल तथा मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:- (1) इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में एक स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 24 जुलाई, 2004 से प्रवृत्त होगा।

2. मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना:- मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना की जाएगी और मद्रास उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश, जिन्हें उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर नामित करेगा, जिनकी संख्या में पांच से कम नहीं होगी, मदुरै पीठ में बैठेंगे एवं तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी,

तिरुनेलवेली, तूतीकोरन, मदुरै, टिंडुगल, रामनाथापुरम, विरुद्धुनगर, शिवगंगा, पुङ्कोट्टाई, तंजावूर, नामपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बालूर और करूर ज़िलों में दर्ज होने वाले मामलों के संबंध में कुछ समय के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

तथापि, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार से आदेश दे सकेंगे कि इनमें से किसी भी ज़िले में दर्ज किसी एक मामले या मामलों की श्रेणी की सुनवाई चैनई में ही होगी।

नई दिल्ली,
दिनांक 6-7-2004

राष्ट्रपति

[फ्र. सं. के-11018/5/98-यूएस-I]

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2004

G.S.R. 446(E).—The following Order made by the President under sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) is hereby published as required by that sub-section namely :-

THE MADRAS HIGH COURT (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT MADURAI) ORDER, 2004

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), the President, after consultation with the Governor of Tamil Nadu and the Chief Justice of the Madras High Court, is pleased to make the following Order, namely:-

- 1. Short title and commencement :** (1) This Order may be called the Madras High Court (Establishment of a Permanent Bench at Madurai) Order, 2004.
 (2) It shall come into force on 24-7-2004.

2. Establishment of a permanent bench of the Madras High Court at Madurai :-

There shall be established a permanent bench of the Madras High Court at Madurai, and such Judges of the Madras High Court, being not less than five in number, as the Chief justice of that High Court may, from time to time nominate, shall sit at Madurai in order to exercise the jurisdiction and powers for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the districts of Kanyakumari, Tirunelveli, Tuticorin, Madurai, Dindugal, Ramanathapuram, Virudhunagar, Sivaganga, Pudukkottai, Thanjavur, Nagapattinam, Tiruchirappalli, Perambalur and Karur in the State of Tamil Nadu:

Provided that the Chief Justice of that High Court may, in his discretion, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Chennai.

New Delhi,
The 6th July, 2004

PRESIDENT

[F. No. K-11018/5/98-US-I]
Dr. P. K. SETH, Jt. Secy.